खाकी

किसान सत्याग्रह की बंद गली में राजकीय हिंसा का प्रवेश न हो जाए

विकास नारायण राय

कुंडली, टीकरी और शाजहांपुर में जमा किसान जत्थेबंदियों के कानून-व्यवस्था प्रबंधन को लेकर हरियाणा पुलिस के अच्छे दिन और कितने दिन चलते रहेंगे, कह पाना मुश्किल है। फिलहाल तो राज्य पुलिस एक संगठित लेकिन पूरी तरह अनुशासित आन्दोलन, जो मुख्यत: पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों से संचालित है, को लेकर आश्वस्त रही है कि उनका कोई भी सदस्य हिंसक या आपराधिक गतिविधियों की ओर नहीं मुड़ सकता। यहाँ तक कि पुलिसवाले उन्हीं लंगरों में बेझिझक खाते-पीते भी देखे गए हैं जो आन्दोलनकारियों के लिए जन-समर्थन से चलाये जा रहे हैं।

इसी हरियाणा पुलिस ने खट्टर सरकार के पिछले कार्यकाल में राज्य के देहातों से ही निकले दो बेहद हिंसक दौर देखे हैं। 2016 में जाट आरक्षण आन्दोलन के दौरान लगभग एक हफ्ता प्रदेश के एक हिस्से में अराजक तत्वों का राज रहा जबकि कानून-व्यवस्था नदारद दिखी। लूट, आगजनी और हत्या के उस उबाल को काबू में आने तक लगभग तीन दर्जन लोग जान गँवा बैठे थे। इसी तरह 2019 में राम-रहीम को बलात्कार के आरोप में सजा होने पर उसके अनुयायियों के पंचकुला में तांडव से निपटने में पुलिस बलों की गोलियों से भी लगभग इतने ही लोग मारे गए थे। इस पैमाने की राज्य हिंसा तभी होगी जब सम्बंधित एजेंसियों ने पहले स्थिति पर नियंत्रण खो दिया हो।

हरियाणा पुलिस के अच्छे दिन और कितने दिन चलते रहेंगे, कह पाना मुश्किल है

उपरोक्त स्थितियों के मुकाबले वर्तमान किसान जमावड़ा न केवल अंतर्राज्यीय स्वरूप वाला है बल्कि इसमें शामिल पुरुष, स्त्री, बच्चों, बूढ़ों की विशाल संख्या भी कानून-व्यवस्था की एजेंसियों को इन्हें रोकने के लिए भारी बल प्रयोग की इजाजत सामान्यत: नहीं देगी। यदि ऐसा होने दिया गया तो परिणाम मोदी शासन के लिए राजनीतिक आत्महत्या सरीखा होगा।

दिल्ली की सरहदों पर भयंकर शीतलहरी के बीच डटा यह अभूतपूर्व किसान आन्दोलन, जो शांतिपूर्ण कलेवर में आठवें हफ्ते में प्रवेश कर चुका है, स्वयं गांधी के लिए भी ईर्ष्या का सबब कहा जाना चाहिए। लेकिन डर है, मोदी सरकार से समझौता बैठकों के तमाम दौर बंजर रहने से कहीं इसकी नियति हिंसक दौर की ओर बढ़ने की न होती जाए। फिलहाल इस आन्दोलन ने, राजधानी की सीमा पर आ धमकने और सरकार से अंतहीन वार्ताओं के क्रम में दृढ़ता दिखाने से अपना दबाव बनाया हुआ है। उसे गति देने के लिए वे गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हजारों ट्रैक्टरों के साथ प्रवेश की घोषणा कर रहे हैं। क्या यह राज्य हिंसा के कहर को खुला अवसर देने जैसा सिद्ध होगा?

गाँधी जी से सारी दुनिया अहिंसा की प्रेरणा लेती है। लेकिन अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध उनके भी सत्याग्रह आन्दोलन हिंसा की चपेट में आने से बच नहीं पाते थे। महज शासकों की दमनकारी हिंसा ही नहीं, स्वयं आन्दोलनकारियों के बीच से भी जब-तब हिंसा फूट पड़ती थी- जलियांवाला बाग, असहयोग, चौरी चौरा, सविनय अवज्ञा, भारत छोडो, करो या मरो, जैसे राष्ट्रीय आन्दोलन के तमाम दौर इसके साक्षी रहे।

हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के जमीनी संघर्ष का एक इतिहास रहा है। हरित क्रान्ति की कृषि लहर के आर्थिक और राजनीतिक फायदे उन्हें कहीं से उपहार स्वरूप नहीं पकड़ा दिए गए। समय-समय पर वे भागीरथी आन्दोलनों में उतरे ताकि यह सूखने न पाए। अस्सी के दशक के, हरियाणा में चौधरी देवी लाल के नेतृत्व में उग्र 'रास्ता रोको' आन्दोलन, पश्चिम उत्तर प्रदेश में महेंद्र सिंह टिकैत के गन्ना कीमत को लेकर लम्बे प्रदर्शन और पंजाब में हरचंद सिंह लोंगोवाल के 'धर्म युद्ध' के दूरगामी सबक आज की कॉर्पोरेट राजनीति करने वालों को भी नहीं भूलने चाहिए।

मोदी सरकार की घोषित नीति किसानों की आय दोगुना करने और एमएसपी जारी रखने की है। उसके नीतिकारों को समझना होगा कि इन मसलों पर किसानों की अपनी समझ पक्की हो चुकी है। उन्होंने हड़बड़ी में लाये किसान विरोधी बिलों की वापसी और एमएसपी गारंटी पर अड़े रह कर पीछे जाने के अपने सारे रास्ते बंद कर लिए हैं। उन्होंने इसे अपने आर्थिक और राजनीतिक वजूद की निर्णायक लड़ाई बना लिया है।

दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की भाजपा नियंत्रित पुलिस और अमित शाह के केन्द्रीय पुलिस बल आन्दोलन के दिल्ली प्रवेश को बलपूर्वक रोकने में समर्थ हो सकते हैं लेकिन राष्ट्र इसके खूनी परिणामों के लिए जिम्मेदार लोगों को शायद ही कभी माफ कर सके।

(पूर्व डायरेक्टर, नेशनल पुलिस अकादमी, हैदराबाद)

राष्ट्रीय

राष्ट्रवादी वैक्सीन पर इतनी बदमाशी ठीक नहीं

यूसुफ किरमानी

कोरोना वैक्सीन पर इतनी ज़लालत देश के लोगों को झेलनी पड़ेगी, इसकी उम्मीद नहीं थी।

भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर (DGCI) ने 3 जनवरी 2021 को कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड (Covishield) और कोवैक्सीन (COVAXIN) को भारत में इस्तेमाल की अनुमति दे दी। दोनों वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल अभी पूरा तक नहीं हुआ।

आनन-फ़ानन में 5 जनवरी को इसका परीक्षण भी शुरू हो गया। भाजपा शासित मध्यप्रदेश के भोपाल शहर में सैकड़ों लोगों को साढ़े सात सौ रूपये देकर कोवैक्सीन लगाई गई और सभी भयंकर बीमार पड़ गए। उन लोगों को इसके साइड इफ़ेक्ट की जानकारी पहले से नहीं दी गई थी। इसका शिकार भोपाल के गैस पीड़ित भी हुए।

कोविशील्ड वैक्सीन को ब्रिटेन की ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राज़ेनका (AstraZeneca) मिलकर तैयार कर रही हैं। इसमें मॉडर्ना का भी सहयोग है। कोविशील्ड का अभी तीसरे चरण का ट्रायल पूरा नहीं हुआ है। कोवैक्सीन को हैदराबाद की कंपनी भारत बॉयोटेक तैयार कर रही है।

कोविशील्ड वैक्सीन भारत में सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंडिया बनाएगा और सप्लाई करेगा। यह तथ्य याद रखिए दोनों वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल बाकी है। भारत बॉयोटेक का 2 जनवरी को सार्वजनिक बयान है कि उसने तीसरे चरण के लिए 23000 वॉलंटियर्स तैयार कर लिए हैं, जिन्हें ये वैक्सीन लगेगी।

सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंडिया के मालिक अदार पूनावाला हैं।

3 जनवरी को ही अदार पूनावाला ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बिल गेट्स का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा किया है। अब कुछ बातें खटक रही हैं।

दोनों वैक्सीन का तीसरे चरण ट्रायल पूरा नहीं हुआ है। फिर भी आपने भोपाल में टीकाकरण शुरू कर दिया।

क्या ये वैक्सीन सबसे पहले पीएम मोदी, अदार पूनावाला, उनके पिता साइरस पूनावाला, मिलिंडा गेट्स, बिल गेट्स को खुद नहीं लगवानी चाहिए? क्या कोवैक्सीन सबसे पहले भारत बायोटेक के मालिक को नहीं लगनी चाहिए। लेकिन कोवैक्सीन की पहली डोज़ हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज को दी गई थी और अगले दिन वो कोरोना पॉज़िटिव निकले। हरियाणा के सरकारी अस्पताल छोड़कर गुड़गाँव के फ़ाइव स्टार जैसे मेदांता अस्पताल में 15 दिनों तक इलाज के बाद बाहर आए हैं। इससे भी सबक़ नहीं लिया गया और भोपाल में बड़े पैमाने पर परीक्षण किया गया।

प्रधानमंत्री मोदी वैक्सीन सप्लायर सीरम कम्पनी के मालिक अदार पूनावाला के साथ

ख़ैर हम बात कर रहे हैं अदर पूनावाला और दोनों वैक्सीन लाने की जल्दबाज़ी पर।

अमेरिका ने फाइजर (Pfizer BioNTech) कंपनी की वैक्सीन को वहाँ लगाने की अनुमति दी। लेकिन इस कंपनी ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और हेल्थ सेक्रेटरी का शुक्रिया अदा नहीं किया। वजह साफ़ है कि अपनी वैक्सीन बेचने के लिए फाइजर कंपनी को किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की सिफ़ारिश या मेहरबानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अमेरिकी हेल्थ सिस्टम पारदर्शी है। वहाँ कुछ छिपाकर माल बेचने का चलन नहीं है। भारत में अदार पूनावाला या भारत बॉयोटेक को प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद या संरक्षण क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि भोपाल जैसी घटना पर मचे शोर को थामा जा सके।

इन दोनों की हरकत भूल गया देश

भारत में नोटबंदी हुई तो दो चीज़ें या दो कंपनियाँ सामने आईं थीं।

चाइनीज़ कंपनी पेटीएम और मुकेश अंबानी यानी रिलायंस का जिओ।

दोनों कंपनियों ने अपनी लॉन्चिंग का जो पहला विज्ञापन दिया उसमें प्रधानमंत्री मोदी का फोटो लगाकर धन्यवाद देने के साथ शुरूआत की गई। जनता को संदेश दिया गया कि इस प्रोडक्ट पर मोदी जी की "कृपा" है।

भारत में कई चाइनीज़ कंपनियाँ बंद हुईं पर पेटीएम आजतक बंद नहीं हुआ। पेटीएम अब हम लोगों की ज़िन्दगी में डालडा या रिफाइन्ड तेल की तरह है। उसे हर चीज की ख़रीददारी में अनिवार्य या मजबूर करने की गहरी साज़िश रची गई है। पेटीएम के कंपनी डिक्लरेशन में आज भी दर्ज है कि अगर आपके पैसे या खाते से कोई घपला होता है तो पेटीएम ज़िम्मेदार नहीं होगा।

सोचिए भारतीय उपभोक्ताओं के पैसे को किस तरह दाँव पर लगा दिया गया। कहीं कोई विरोध नहीं, कहीं कोई जवाबदेही नहीं। अभी हम वो बात करने ही नहीं वाले कि किस तरह दिल्ली-ग़ाज़ियाबाद-मेरठ रैपिड रेल का साढ़े पाँच किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाने का ठेका चीन की कंपनी शंघाई टनल इंजीनियरिंग लिमिटेड को दिया गया है।

और जिओ...।

जिओ को सफल करने के लिए ट्राई के नियम किस तरह बदले गए। वो आप लोगों को याद होगा। पहले फ्री डेटा आया। आपको इंटरनेट का आदी बनाया गया। फिर डेटा थोड़ा महँगा किया गया और अब क्या रेट है, आप लोगों को मालूम ही होगा। इसका नतीजा क्या निकला कई टेलीकॉम कंपनियाँ डूब गईं। कुछ घाटे में हैं। टेलीकॉम बिज़नेस जिस तेज़ी से फलफूल रहा था, वो बर्बाद हो गया। बीएसएनएल और एमटीएनएल, इस देश की सबसे पुरानी और नामी सरकारी कंपनियों को 4जी स्पेक्ट्रम नहीं दिया गया। उनको प्राइवेट कंपनियों से मुक़ाबला नहीं करने दिया गया। दोनों सरकारी सबसे धनी टेलीकॉम कंपनियाँ बिकने जा रही हैं।

ड्रग कंट्रोलर भी जल्दी में है

अब वापस वैक्सीन पर लौटते हैं। एक और तथ्यात्मक बात बताता चलूँ कि प्रधानमंत्री अदार पूनावाला की कंपनी सीरम इंस्टिट्यूट 28 नवम्बर 2020 को घूमकर आये थे और कंपनी की बहुत तारीफ़ की थी। उस मुलाक़ात का नतीजा आख़िरकार 3 जनवरी 2021 को आ ही गया। लेकिन 5 जनवरी को भोपाल में जो कुछ हुआ, वह शर्मसार करने वाला है।

बहरहाल, हमें मोदी और अदार पूनावाला की नीयत या रिश्ते पर कोई शक नहीं है। हमें भारत बॉयोटेक पर भी भरोसा है। बस, बात इतनी सी है कि बिना तीसरे चरण का ट्रायल पूरा हुए दोनों वैक्सीन को लाने की जल्दी क्यों?

आप यही वैक्सीन लाते, लेकिन तीसरे दौर का ट्रायल तो पूरा होने देते।

भारत के ड्रग कंट्रोलर वी. जी. सोमानी ने बहुत अजीबोग़रीब तरीक़े से 3 जनवरी को वैक्सीन को अनुमति देने के फ़ैसले का अनुमोदन किया है। वह हैरान कर देने वाला है। उन्होंने रविवार को सार्वजनिक बयान में कहा - किसी वैक्सीन में मामूली कमी रहेगी तो हम उसे अनुमति नहीं देंगे। सभी वैक्सीन 110 प्रतिशत सुरक्षित हैं। इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़रूर हैं, जिनमें मामूली बुखार, दर्द और एलर्जी बहुत आम हैं। लेकिन ये आरोप ग़लत है कि इस वैक्सीन से कोई नामर्द हो जाएगा।

भारत के ड्रग कंट्रोलर सोमानी किस आधार पर और क्यों वैक्सीन के 110 प्रतिशत सुरक्षित होने की ज़िम्मेदारी ले रहे हैं, कोई नहीं जानता। आप जिन पर परीक्षण करने जा रहे, क्या आपने उन्हें पूरी जानकारी अब तक दी। भोपाल के लोगों का कहना है कि उनके शरीर में टीका ज़बरन ठेला गया है।

बिल गेट्स हैं सर्वशक्तिमान

अब बिल गेट्स पर आते हैं। दुनिया के अमीरों में शुमार।

भारत की ग़रीबी, भुखमरी और बाल कुपोषण से जनाब बिल गेट्स को बहुत हमदर्दी है। अचानक 2014 से बिल गेट्स भारत को इतनी मदद कर देते हैं जितना यूपी जैसे राज्य का सालाना बजट होता है। भारत में उनकी संस्था बिल एंड मिलिंडा गेट्स फ़ाउंडेशन के ज़रिए काम करती है। मिलिंडा गेट्स बिल गेट्स की पत्नी हैं। भारत सरकार बिल गेट्स को कई राष्ट्रीय सम्मानों से नवाज चुकी है।

इनकी फ़ाउंडेशन अमेरिका दवा कंपनी मॉडर्ना (mRNA) के कई सारे प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर आर्थिक मदद करती है। बताता चलूँ कि मॉडर्ना के असली मालिक बिल गेट्स नहीं हैं, लेकिन वे इसके असली मालिक से भी बढ़कर हैं।

....तो मॉडर्ना ही ब्रिटेन की ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राज़ेनका द्वारा बनाई जा रही कोविशील्ड को भी बनाने में मदद कर रही है। यह भी कह सकते हैं कि कोविशील्ड दरअसल मॉडर्ना का भी उत्पाद है या बाकी देशों में इसे मॉडर्ना अपने ब्रैंड के तहत बेचेगी। अलग-अलग देश में अलग-अलग नाम। धंधा है, यही चलेगा। स्वीकार्य है।

बिल गेट्स ने 8 दिसम्बर 2020 को सिंगापुर के फिनटेक फ़ेस्टिवल में कहा था - दुनिया में कोरोना की वैक्सीन अप्रैल 2021 से पहले नहीं आने वाली है।...

लेकिन भारत में जल्दी मची हुई है। 5 जनवरी को भाजपा के नेताओं और मोदी कैबिनेट के मंत्रियों ने दोनों वैक्सीनों को राष्ट्रवादी वैक्सीन घोषित कर दिया। तीसरे चरण का कोई अतापता नहीं है। अगर भाजपा तीसरे चरण का इंतज़ार करती तो शायद वैक्सीन राष्ट्रवादी न बन पाती।

बिल गेट्स से बेहतर कोई नहीं जानता कि किस कंपनी की वैक्सीन कब आएगी, क्योंकि हर कंपनी के मददगार या फ़ाइनैंसर बिल गेट्स या उनकी फ़ाउंडेशन ही तो हैं। मॉडर्ना के ज़रिए बिल गेट्स सब जगह विराजमान हैं।

लेकिन भारत में तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन आ पहुँची है। भोपाल से शुरूआत कर दी गई। बाकी देश के लिए पूरा प्लान तैयार है। कई राज्यों में सेंटर तक तक बन गए हैं कि वैक्सीन कहाँ लगाई जाएगी। देशभर के ज़िलों में सभी डीएम और एसडीएम की देखरेख में पूरा सिस्टम काम शुरू कर चुका है। पंचायतों तक इस अभियान में शामिल किया गया है।

ध्यान रहे मैं दोनों वैक्सीन पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा हूँ। बस, सवाल इन्हें लगाने की हड़बड़ी पर है। सवाल है कि तीसरा ट्रायल पूरा हुए बिना भारत के लोगों को क्यों शिकार बनाया जा रहा है? क्या भारत के लोग आपको बंदर, चूहे, बिल्ली नज़र आते हैं? भोपाल में जो कुछ हुआ, वह जल्दबाज़ी का नतीजा नहीं है तो और क्या है? वैक्सीन लगवाएँ लेकिन सरकार से सवाल भी करें।

(वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक)